डाक पंजीयन क्रमांक - म.प्र./भोपाल/4-357/2024-26

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

किसान कल्याण वर्ष-2026
समृद्ध किसान-समृद्ध प्रदेश

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

प्रकाशन दिनांक 1 जुलाई, 2026, डिस्पेच दिनांक 1 जुलाई, 2026

| वर्ष 70 | अंक 03 | भोपाल | 1 जुलाई, 2026 | पृष्ठ 12 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/- |

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने NAFED के ई-ऑक्शन पोर्टल NAFEX.in का शुभारंभ किया

देश की एकता-अखंडता के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को बलिदान दिवस पर शत्-शत् नमन

2014 में बंद होने के कगार पर खड़ा NAFED आज मोदी सरकार में रु. 500 करोड़ के मुनाफे के साथ 74 लाख किसानों की सेवा कर रहा

बिचौलिए होंगे खत्म, किसान के पसीने की कमाई 48 घंटे में सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचेगी

अगले 2 वर्षों में दलहन का एक-एक दाना सीधे किसानों से खरीदेगा NCCF और NAFED

किसानों के बच्चों की उच्च शिक्षा और करियर के लिए NAFED की छात्रवृत्ति शुरू, मुनाफे का एक हिस्सा किसान परिवारों को दी जाएगी

नई दिल्ली | केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NAFED) के ई-ऑक्शन पोर्टल NAFEX.in का शुभारंभ किया। इस अवसर पर केन्द्रीय कृषि, किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, सहकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर, सहकारिता सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी और NAFED के अध्यक्ष श्री जेठाभाई अहीर सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि NAFED ने आज चार प्रमुख पहलों की शुरुआत की है, जिसमें NAFEX.in, दृष्टि, ईआरपी और NAFED कल्याण शामिल हैं। उन्होंने कहा कि NAFEX.in सहित अन्य पहलें काफी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वर्ष 2014 में NAFED बंद होने की कगार पर था, लेकिन आज इन प्रयासों के कारण NAFED 30,000 करोड़ रुपये के टर्नओवर और 500 करोड़ रुपये के मुनाफे के साथ देश के 74 लाख से अधिक किसानों की सेवा कर रहा है। श्री शाह ने कहा कि जब NAFED गहरे आर्थिक संकट में था, तब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने इसे पूरी पारदर्शिता के साथ चलाने का निर्णय लिया था। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने आर्थिक सहायता प्रदान कर NAFED को एक बार फिर मजबूती से खड़ा कर दिया है।

श्री अमित शाह ने कहा कि आज NAFED उत्पादन और खरीद दोनों में काफी बढ़ोत्तरी कर चुका है। देश को दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए NCCF और NAFED को सीधे किसानों से दलहन का एक-एक दाना खरीदने की दिशा में और भी तेजी से आगे बढ़ना है। इससे किसानों को उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा, तो दलहन की खेती का रकबा अपने आप बढ़ेगा और देश दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा।

केन्द्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में हमने दलहन, मक्का तथा अन्य उत्पादों की सीधी खरीद के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया है। अब इस इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे तक पहुंचाना है। श्री शाह ने कहा कि NAFED और NCCF को पूरी दृढ़ता और पारदर्शिता के साथ काम करना होगा, तभी परिणाम मिलेंगे। उन्होंने कहा कि हम सुनिश्चित करेंगे कि अगले दो वर्षों के भीतर सभी किसान इन दोनों संगठनों को सीधे दलहन बेच सकें और उन्हें भुगतान भी सीधे उनके खाते में मिले।

श्री अमित शाह ने कहा कि आज NAFED केवल कृषि उत्पादों की खरीद तक सीमित नहीं रहा है। विगत तीन वर्षों में NAFED ने जैविक खेती, बीज उत्पादन, खुदरा कारोबार, जैव उर्वरक निर्माण, खाद्य सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय व्यापार जैसे क्षेत्रों में बहुत अच्छा कार्य किया है, जिससे NAFED की प्रासंगिकता भी बढ़ी है और मुनाफा भी बढ़ा है। उन्होंने कहा कि जब सहकारिता मंत्रालय बना था, तब NAFED का टर्नओवर 20,000 करोड़ रुपये था, जो अब बढ़ कर 30,000 करोड़ रुपये हो चुका है। उन्होंने विश्वास जताया कि अगले दो वर्षों में यह टर्नओवर बढ़कर 50,000 करोड़ रुपये के पार हो जाएगा। श्री शाह ने कहा कि NAFED का शुद्ध मुनाफा 139 करोड़ रुपये से बढ़कर 405 करोड़ रुपये हो गया है और नेटवर्थ 358 करोड़ रुपये से बढ़कर 2,050 करोड़ रुपये हो गई है। उन्होंने कहा कि NAFED आज एक मजबूत, आर्थिक रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर संगठन के रूप में उभरा है। अब समय है कि NAFED और NCCF पूरी पारदर्शिता के साथ दलहन तथा अन्य फसलों का एक-एक दाना सीधे किसानों से खरीदें, बिचौलियों के पूरे तंत्र को समाप्त करें और मुनाफा जिन किसानों का हक है, वह उन तक अवश्य पहुंचाएं।

सहकारिता मंत्री ने कहा कि NAFED ने अपने मुनाफे का 1% किसान परिवारों के बच्चों की उच्च शिक्षा और करियर विकास के लिए छात्रवृत्ति देने का निर्णय लिया है। यह व्यवस्था किसानों के बच्चों को उच्च शिक्षा और करियर बनाने में आने वाली दिक्कतों को दूर करने में सहयोग करेगी।

अपने संबोधन की शुरुआत में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री और भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री शाह ने कहा कि आज ही के दिन डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने 'एक राष्ट्र, एक विधान, एक प्रधान' के सूत्र को चरितार्थ करने और देश को एकजुट रखने के लिए बलिदान दिया था। उन्होंने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस राष्ट्र के बड़े नेताओं में शुमार हैं। उन्होंने जीवन में कुछ भी प्रसिद्धि के लिए नहीं किया और जो किया उसके दूरगामी परिणाम इस देश के लिए शुभ साबित हुए। श्री शाह ने कहा कि भारत के विभाजन के समय अंग्रेजों से लड़ाई लड़ कर डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने सुनिश्चित किया था कि पश्चिम बंगाल भारत में रहे। इसी कारण आज पश्चिम बंगाल भारत का अभिन्न अंग बना हुआ है। गृह मंत्री ने कहा कि आजादी के बाद कश्मीर में अनुच्छेद 370 लागू किया गया, जिसकी वजह से कश्मीर का राष्ट्रध्वज और संविधान अलग था। श्री शाह ने कहा कि यह संकल्पना भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत खतरनाक थी। तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने एक आंदोलन छेड़ा कि एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं रहेंगे। इसके लिए उन्होंने दिल्ली से कश्मीर तक मार्च किया और कहा कि कश्मीर भारत का हिस्सा है। कश्मीर जाने के लिए उन्होंने कोई परमिट लेने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। कश्मीर की जेल में ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी की संहेदास्पद मृत्यु हो गई। श्री शाह ने कहा कि कश्मीर के मुद्दे पर ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तत्कालीन सरकार के उद्योग मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। गृह मंत्री ने कहा कि आज श्यामा प्रसाद जी का सपना साकार हो चुका है। अनुच्छेद 370 समाप्त हो चुका है और उनकी बनाई पार्टी की सरकार गंगोत्री से लेकर बंगाल के गंगासागर तक है। उन्होंने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और भारतीय संस्कृति के प्रखर हिमायती थे।

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

भोपाल, 1 जुलाई, 2026

प्रकृति हमारी मां है, इसे रासायनिक उर्वरकों से बचाएं, प्राकृतिक खेती अपनाएं : प्रधानमंत्री श्री मोदी

मध्यप्रदेश प्राकृतिक खेती अपनाने वाले राज्यों में है सबसे अव्वल : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

फसलों में कीटनाशक और रासायनिक खाद का उपयोग नुकसानदेह

प्राकृतिक खेती में अत्यंत सहायक है गौमाता के गोबर और गौमूत्र से बनी खाद

गाय प्राकृतिक खेती में सर्वाधिक मददगार, गाय पालने वाले किसान को हर महीने देंगे 1100 रुपए

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने पश्चिम बंगाल से किया किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त का अंतरण

सिपेट में हुई प्राकृतिक खेती कार्यशाला सह कृषक संगोष्ठी

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने किसान सम्मान निधि अंतरण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री मोदी के संबोधन के सीधा प्रसारण का श्रवण किया

भोपाल, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि प्रकृति हमारी माता है और हम सब इसकी संताना। अपनी धरती माता को हमें रासायनिक उर्वरकों और हानिकारक कीटनाशकों से बचाना है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती का पहला लक्ष्य मिट्टी में जैविक गतिविधियों को बढ़ाना है। यह खेती मिट्टी में केंचुए और सूक्ष्म जीव पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाती है। इससे भूमि की उर्वरता लंबे समय तक बनी रहती है। स्वस्थ मिट्टी ही समृद्ध कृषि की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि किसान भाई अधिक से अधिक प्राकृतिक और जैविक खेती अपनाएं। इससे हमारी धरती माता की सेहत भी बनी रहेगी और इससे उपजे अनाज के पोषण से हम सब भी स्वस्थ रहेंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी को पश्चिम बंगाल से पीएम किसान सम्मान निधि के अंतरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा पश्चिम बंगाल के हुगली स्थित तारकेश्वर से देश के 9.40 करोड़ से अधिक किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त के रूप में कुल 18 हजार 880 करोड़ रुपए पात्र किसानों के खातों में अंतरित किए। कार्यक्रम से प्रदेश के 81 लाख से अधिक किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में 1640 करोड़ रूपए प्राप्त हुए हैं।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि के सभी लाभार्थियों से अपील करते हुए कहा कि हमें धरती माता को बचाना है। हमें अपने बच्चों को बंजर जमीन नहीं देनी है। भारत सरकार खेत बचाओ अभियान चला रही है। हमें प्राकृतिक खेती अपनाकर रासायनिक खाद और कीटनाशकों का उपयोग कम से कम करना है। देशभर के किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ें, दूसरों को भी प्रेरित करें और खेतों की मिट्टी की जांच करवाएं। हम सभी मिलकर धरती मां की रक्षा करें। हम केमिकल से धरती मां को नहीं मार सकते हैं। हमें उसे बचाना ही होगा। केंद्र सरकार ने विकसित भारत @2047 का संकल्प लिया है, इसमें देशवासियों का सहयोग बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने देश के किसानों से कहा कि जिस तरह प्राकृतिक खेती से मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है, उसी तरह योग करने से हमारा तन-मन स्वस्थ रहता है। प्रधानमंत्री ने सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (21 जून) की अग्रिम बधाई देते हुए कहा कि सभी देशवासी योग करें, क्योंकि योग ही स्वस्थ जीवन की कुंजी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरूआत फरवरी 2019 में हुई थी। इसके तहत हर साल छह हजार रूपये, दो-दो हजार की तीन समान किश्तों में किसान भाईयों को दिए जाते हैं। अब तक प्रदेश के किसान भाईयों को 22 किश्तों में 33 हजार 800 करोड़ रूपये मिल चुके हैं। शनिवार को 23वीं किश्त का अंतरण किया गया। पश्चिम बंगाल में हुए इस कार्यक्रम का देशभर में सीधा प्रसारण किया गया।

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में साकार होते देख रहे है रामराज्य की संकल्पना

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बरखेड़ीकला स्थित राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान (सिपेट) में 'प्राकृतिक खेती कार्यशाला सह कृषक संगोष्ठी' में पहुंचकर प्रधानमंत्री श्री मोदी के संपूर्ण संबोधन का श्रवण किया। मुख्यमंत्री ने संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हम रामराज्य की संकल्पना को साकार होते देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने गांव, गरीब, अन्नदाता किसान, युवा और नारी सहित सभी वर्गों के कल्याण से विश्व में भारत की अलग ही पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मध्यप्रदेश को दो-दो नदी जोड़ो परियोजनाओं की सौगात दी है। इससे प्रदेश के किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलेगा और उनके सूखे खेतों में फसलें लहलहाएंगी। आज देश के हर गांव-कस्बे तक बिजली, पानी, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं का जाल बिछ रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने ही देश के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देने की योजना प्रारंभ की है। यह हमारे अन्नदाता के अथक परिश्रम का सम्मान है। मध्यप्रदेश सरकार भी किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषक कल्याण वर्ष मना रही है। हम किसानों के कल्याण के लिए हर जरूरी कदम उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने पीएम किसान सम्मान निधि पाने वाले प्रदेश के सभी किसानों को बधाई दी और प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील की। इस अवसर पर विधायक श्री रामेश्वर शर्मा, जनप्रतिनिधि श्री रविन्द्र यति, अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त श्री अशोक बर्णवाल, आयुक्त श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव, कलेक्टर भोपाल श्री प्रियंक मिश्रा सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में किसान बंधु उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि फसलों में कीटनाशक और रासायनिक खाद का उपयोग नुकसानदेह है। इससे कैंसर जैसी कई घातक बीमारियां जन्म लेती हैं। सरकार ने किसानों को पुन: प्राकृतिक खेती से जोड़ने के लिए पहल की है, इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। आज हमारा मध्यप्रदेश देश में सर्वाधिक प्राकृतिक खेती करने वाला राज्यों में अव्वल स्थान पर है। प्राकृतिक खेती की उपज को उचित दाम दिलवाने के लिए राज्य सरकार संकल्पित है। हमारी प्राकृतिक खेती से दुनिया लाभान्वित हों, इसी भाव से कार्य करते हुए प्रदेश में तेजी से गोशालाओं का विस्तार किया जा रहा है। हमारी गौमाता प्राकृतिक खेती में सबसे अधिक मददगार प्राणी है। किसान गोबर और गौमूत्र से खाद बनाकर खेतों में डालें, इसी उद्देश्य से गौपालक किसानों को हमारी सरकार हर महीने 1100 रुपए प्रति गाय की दर से आर्थिक सहायता दे रही है। गौ-आधारित कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करती है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि किसानों को उपज का सही दाम मिले, इसके लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। पहले सोयाबीन पर भावांतर योजना के माध्यम लाभ दिया, उसके बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर 40 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देकर किसानों से गेहूं उपार्जित किया। राज्य सरकार ने किसानों से गेहूं का एक-एक दाना खरीदकर उन्हें प्रति क्विंटल 2625 रुपए भुगतान किया है। हमारी सरकार प्राकृतिक खेती के जरिए किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है। इससे धरती माता की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी और विदेशी रासायनिक खाद पर निर्भरता भी घटेगी। प्रदेश के नागरिकों को प्राकृतिक तरीके से उगाए देसी ज्वार, बाजरा और गेहूं-चना का स्वाद मिलेगा। किसानों को दूध उत्पादन से भी जोड़ा जा रहा है। इसका दोहरा लाभ आय बढ़ाने के साथ-साथ प्राकृतिक खाद निर्माण में भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती में मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ती है। कम सिंचाई में भी फसल अच्छी होती है। प्राकृतिक खेती केवल खेती की एक तकनीक ही नहीं, धरती माता, किसान और उपभोक्ता- तीनों के स्वास्थ्य की रक्षा का अभियान है। जलवायु परिवर्तन के दौर में यह एक महत्वपूर्ण समाधान है। उन्होंने कहा कि भावी पीढ़ियों के लिए जल बचाना हम सबका कर्तव्य है, हम सबको जल संरक्षण के लिए आगे आना चाहिए।

प्रदेश में प्राकृतिक खेती

मध्यप्रदेश देश का अग्रणी कृषि राज्य है। गेहूं, सोयाबीन और दलहन उत्पादन में प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका है। मध्यप्रदेश प्राकृतिक खेती में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में 3 लाख एकड़ में जैविक/प्राकृतिक खेती की जा रही है। प्रदेश के 56 कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि महाविद्यालयों द्वारा प्राकृतिक खेती के लिए तकनीकी मदद और प्रशिक्षण किसानों को दिए जा रहे हैं। सरकार प्रदेश में एक हजार से अधिक बॉयो रिसर्च सेंटर बना रही है। ये सेंटर प्राकृतिक खेती में किसानों की मदद करेंगे। प्राकृतिक खेती के उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है। देश और विदेश में इनके लिए विशेष बाजार विकसित हो रहे हैं। ब्रांडिंग और प्रमाणन से किसानों को अधिक मूल्य मिलता है। यह आय वृद्धि का बड़ा अवसर है। किसानों की मदद के लिए 3 हजार से ज्यादा कृषि सखी, 200 से अधिक कृषि वैज्ञानिकों को भी प्रशिक्षित किया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि किसानों की आय बढ़े, लागत घटे और भूमि भी स्वस्थ बने। हर गांव प्राकृतिक खेती का केंद्र बने। समृद्ध मध्यप्रदेश के निर्माण के लिए सरकार इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है।

मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में विकसित की जाए एक हैचरी : मुख्यमंत्री

मछली पालन के लिए प्रदेश में होगा 9 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश

प्रदेश में मोती उत्पादन को किया जाए प्रोत्साहित

मध्यप्रदेश बने मछली बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने की मछुआ कल्याण और मत्स्य विकास विभाग की समीक्षा

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि एकीकृत मत्स्योघोग नीति : 2026 के कारण प्रदेश में मछली पालन सेक्टर में 9 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आ रहा है। प्रदेश में प्राप्त 2 लाख 91 हजार 9 सौ 38 केज के प्रस्तावों के लिए कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं। प्रदेश में मोती उत्पादन को भी प्रोत्साहित किया जाये, इसके लिए अन्य राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिसेस का अध्ययन कर उनका क्रियान्वयन प्रदेश में सुनिश्चित किया जायें। प्रदेश को मछली उत्पादन में आत्म निर्भर बनाना जरूरी है। अगले ढाई साल में हमें मछली बीज अन्य स्थानों से नहीं खरीदना पड़े, इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर विभाग कार्य करे। हर जिले में एक हेचरी आवश्यक रूप से विकसित की जाये। जिलों में मछली बीज आसानी से मिलने से प्रदेश में मछली उत्पादन में और बढ़ोत्तरी होगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यह निर्देश मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग की समीक्षा बैठक में दिए। मंत्रालय में हुई बैठक में मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास राज्य मंत्री श्री नारायण सिंह पवार, मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन, विभाग के सचिव श्री स्वतंत्र कुमार सिंह तथा विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

मछुआ क्रेडिट कार्ड में मध्यप्रदेश, देश में दूसरे स्थान पर- मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में बढ़ रहे मछली उत्पादन को दृष्टिगत रखते हुए कोल्ड चेन तथा अन्य आवश्यक इंफ्रास्टक्चर विकसित किया जाये। ब्रांडिंग और निर्यात के लिए आवश्यक नेटवर्किंग को भी प्रोत्साहित किया जाये। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नदियों के पुनर्जीवन, जलीय जीवों के संरक्षण के लिए सभी संबंधित विभाग परस्पर समन्वय से कार्य करें। जलीय ईको सिस्टम को विकसित करने और जल सम्पदा पर आधारित पर्यटन गतिविधियों को विस्तार देने के लिए भी कार्य योजना बनाई जाये। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में बताया गया कि मछुआ किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत अन्तर्देशीय जल क्षेत्र में मध्यप्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है। राष्ट्रीय स्तर पर अन्तर्देशीय मत्स्य पालन में सिवनी जिले को वर्ष 2023-24 के लिए प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।

सहकारी समितियों के प्रबंधकों को दिया 'ई-विकास' पोर्टल का तकनीकी प्रशिक्षण

हरदा, कृषि विभाग एवं सहकारिता विभाग के संयुक्त समन्वय से जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, हरदा के सभागार में जिले की सहकारी समितियों के प्रबंधकों हेतु 'ई-विकास' पोर्टल के संबंध में एक दिवसीय तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास, हरदा श्री जे.एल. कास्दे ने की।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिले की सभी प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के प्रबंधकों ने सहभागिता की। कार्यक्रम के मुख्य प्रशिक्षक सहायक संचालक कृषि डॉ. भगवत रहे। उन्होने 'ई-विकास' पोर्टल की कार्यप्रणाली, ऑनलाइन डेटा प्रविष्टि, उर्वरक वितरण प्रबंधन, हितग्राही सेवाओं एवं पोर्टल संचालन से संबंधित तकनीकी पहलुओं की विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की। साथ ही पोर्टल के प्रभावी संचालन हेतु आवश्यक प्रक्रियाओं एवं सावधानियों से भी अवगत कराया।

इस अवसर पर जिला विपणन अधिकारी श्री योगेश मालवीय तथा नोडल अधिकारी (सहकारी बैंक) श्री सतीश सितोके विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने सहकारी समितियों के प्रबंधकों को पोर्टल संचालन में आने वाली व्यावहारिक समस्याओं के निराकरण, विभागीय समन्वय तथा किसानों को बेहतर एवं पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने संबंधी आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया।

कार्यक्रम में उप संचालक कृषि श्री कास्दे ने कहा कि शासन की मंशानुसार सहकारी संस्थाओं के कार्यों में पारदर्शिता, दक्षता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ई-विकास प्रणाली का प्रभावी क्रियान्वयन अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने सभी समिति प्रबंधकों को निर्देशित किया कि प्रशिक्षण में प्राप्त तकनीकी ज्ञान का उपयोग करते हुए पोर्टल पर सभी कार्य समयबद्ध एवं त्रुटिरहित रूप से संपादित करें, ताकि किसानों को शासन की योजनाओं एवं सुविधाओं का लाभ बिना किसी असुविधा के प्राप्त हो सके।

उन्होंने आगामी खरीफ सीजन को दृष्टिगत रखते हुए सहकारी समितियों को किसानों की संभावित मांग के अनुसार उर्वरकों का अग्रिम भंडारण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि समितियां उर्वरकों की उपलब्धता एवं वितरण व्यवस्था पर सतत निगरानी रखें, जिससे कृषकों को समय पर पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हो सके तथा वितरण व्यवस्था में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो।

कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों ने विश्वास व्यक्त किया कि ई-विकास पोर्टल के प्रभावी संचालन से सहकारी समितियों की कार्यप्रणाली और अधिक सुदृढ़ होगी तथा जिले के कृषकों को त्वरित, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी।

अपेक्स बैंक प्रशासक ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, टीकमगढ़ की समीक्षा बैठक में दिए निर्देश

टीकमगढ़। अपेक्स बैंक के प्रशासक श्री महेन्द्र सिंह यादव ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, टीकमगढ़ के प्रधान कार्यालय स्थित सभाकक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश सरकार द्वारा घोषित "कृषक कल्याण वर्ष-2026" के उद्देश्यों को साकार करने के लिए सहकारी बैंक एवं प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियाँ पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करें। उन्होंने सदस्यता वृद्धि अभियान, खरीफ-2026 के कृषि ऋण वितरण, ऋण वसूली तथा किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने सहित विभिन्न विषयों की विस्तृत समीक्षा की।

बैठक को संबोधित करते हुए श्री यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार किसानों एवं सर्वहारा वर्ग के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसी क्रम में अपेक्स बैंक द्वारा 14 अप्रैल से 30 जून 2026 तक पूरे प्रदेश में 10 लाख किसानों को सहकारिता से जोड़ने हेतु विशेष सदस्यता महाअभियानसंचालित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि रु. 500 अंशपूंजी एवं रु. 100 सदस्यता शुल्क के माध्यम से किसानों को सहकारी समितियों का सदस्य बनाया जा रहा है, जिससे वे शून्य प्रतिशत ब्याज पर कृषि ऋणसहित सहकारिता की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें। उन्होंने समिति प्रबंधकों एवं जिला बैंकों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया कि सदस्यता अभियान को मिशन मोड में संचालित करते हुए अधिकाधिक किसानों को सहकारी व्यवस्था से जोड़ें तथा इसकी नियमित समीक्षा एवं मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें।

गेहूं उपार्जन की बेहतर व्यवस्थाओं से किसानों को हुई सुविधा

म.प्र. है पंजाब के बाद उपार्जन में दूसरे क्रम पर

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने भेंट कर किसान कल्याण के निर्णयों के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कृषक कल्याण वर्ष 2026 में कृषकों के कल्याण के कार्य निरंतर होंगे। अन्नदाता को सम्मान के साथ उन्हें अधिक से अधिक सुविधाएं देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव से प्रतिनिधि मंडल ने गेहूं खरीदी में मध्यप्रदेश की उपलब्धि के लिए हर्ष व्यक्त करते हुए किसानों के लिए की गई बेहतर व्यवस्था के लिए आभार व्यक्त किया। मध्यप्रदेश ने समर्थन मूल्य पर 13.42 लाख किसानों से 104.36 लाख मे.टन गेहूं का उपार्जन किया गया है। किसान संख्या की दृष्टि से मध्यप्रदेश भारत में प्रथम है। उपार्जन की दृष्टि से पंजाब के बाद मध्यप्रदेश दूसरे स्थान पर रहा है। समर्थन मूल्य 2585 रुपए प्रति क्विंटल के साथ ही 40रुपए बोनस राशि मिलाकर किसान को प्रति क्विंटल 2625 रुपए प्रति क्विंटल के भुगतान की व्यवस्था करवाई गई। किसानों को 27 हजार 196.48 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान प्रदेश में किया जा चुका है। विभिन्न परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण में 4 गुना मुआवजा देने का प्रावधान करने के लिए आभार व्यक्त किया। प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने कहा कि राज्य शासन द्वारा किसानों के हित में लिए गए निर्णय प्रशंसनीय हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव से भेंट कर किसानों ने कृषक हित से संबंधित कुछ सुझाव भी दिए। इनमें मूंग खरीद व्यवस्था और मूंग-उड़द के लिए पंजीयन की प्रक्रिया पूर्ण करवाने, नहरों को तालाबों से जोड़ने के सुझाव शामिल हैं। प्रतिनिधिमंडल में श्री कमल सिंह आंजना, श्री चंद्रकांत गौर के साथ श्री सर्वज्ञ दीवान, श्री लक्ष्मी नारायण पटेल, श्री प्रह्लाद पटेल आदि शामिल थे।

कृषक कल्याण वर्ष के लक्ष्य को साकार करने में सहकारी समितियाँ निभाएँ प्रभावी भूमिका : महेन्द्र सिंह यादव

अपेक्स बैंक प्रशासक ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, छतरपुर की समीक्षा बैठक में दिए निर्देश

छतरपुर। अपेक्स बैंक के प्रशासक श्री महेन्द्र सिंह यादव ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, छतरपुर के प्रधान कार्यालय स्थित सभाकक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश सरकार के "कृषक कल्याण वर्ष-2026" के संकल्प को सफल बनाने में सहकारी समितियाँ और जिला सहकारी बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँ। उन्होंने सदस्यता अभियान, कृषि ऋण वितरण, ऋण वसूली तथा किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने जैसे विषयों की विस्तृत समीक्षा करते हुए निर्धारित लक्ष्यों की समयबद्ध पूर्ति के निर्देश दिए।

श्री यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादवके नेतृत्व में प्रदेश सरकार किसानों एवं सर्वहारा वर्ग के हितों के लिए सतत कार्य कर रही है। इसी उद्देश्य से अपेक्स बैंक द्वारा 14 अप्रैल से 30 जून 2026 तक प्रदेशभर में10 लाख किसानों को सहकारिता से जोड़ने के लिए विशेष सदस्यता महाअभियानसंचालित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि रु. 500 अंशपूंजी एवं रु. 100 सदस्यता शुल्क के माध्यम से किसानों को सहकारी समितियों का सदस्य बनाया जा रहा है, जिससे वे शून्य प्रतिशत ब्याज पर कृषि ऋण सहित सहकारिता की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें।

उन्होंने सभी जिला बैंकों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों एवं समिति प्रबंधकों को निर्देशित किया कि सदस्यता अभियान को जनआंदोलन का स्वरूप देते हुए अधिकाधिक किसानों को सहकारी व्यवस्था से जोड़ा जाए तथा इसकी नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए।

बैठक में खरीफ-2026 के लिए प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से कृषि ऋण वितरण एवं ऋण वसूली की भी समीक्षा की गई। श्री यादव ने कहा कि ऋण की समय पर वसूली से सहकारी बैंक आर्थिक रूप से सुदृढ़ होंगे तथा सहकारी आंदोलन को नई गति मिलेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को खाद, बीज एवं उर्वरक समय पर उपलब्ध कराने में किसी प्रकार की कठिनाई न आने पाए तथा शासन की मंशा के अनुरूप सभी व्यवस्थाएँ पूर्व से सुनिश्चित की जाएँ।

उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के "एक पेड़ माँ के नाम" अभियान का उल्लेख करते हुए सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अपने घर, कार्यस्थल एवं आसपास अधिकाधिक वृक्षारोपण करने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में इस अभियान के अंतर्गत लगभग एक लाख पौधों का रोपण किया जा चुका है। साथ ही उन्होंने अधिकारियों से किसानों को "मन की बात" कार्यक्रम से जोड़ने का भी आग्रह किया, ताकि वे केंद्र एवं राज्य सरकार की किसान हितैषी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकें।

श्री यादव ने अधिकारियों से कहा कि यदि शासन स्तर पर किसी प्रकार की व्यावहारिक समस्या आ रही हो तो उसे तत्काल अवगत कराएँ, जिससे उसके शीघ्र समाधान के लिए आवश्यक पहल की जा सके।

बैठक में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, छतरपुर के प्रशासकश्री करूणेन्द्र सिंहने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि 28 जून तक प्रत्येक शाखा अपने निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप 50 से अधिक किसानों को सदस्य बनाने का कार्य पूर्ण करे।

बैठक के अंत में अपेक्स बैंक के प्रशासकश्री महेन्द्र सिंह यादवका बैंक प्रबंधन एवं बैंक कर्मचारी यूनियन द्वारा शाल, श्रीफल, बुंदेली परंपरा के अनुसार साफा पहनाकर तथा स्मृति-चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया।

बैठक में अपेक्स बैंक के ओएसडी श्री अभय प्रधान, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक टीकमगढ़ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री शिवम शाह, मार्केटिंग ऑफिसर श्री प्रमोद कुमार तिवारी, जिला बैंक छतरपुर के समस्त शाखा प्रबंधक एवं समिति कर्मचारी उपस्थित रहे। बैठक के उपरांत श्री यादव ने बैंक परिसर में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ" एक पेड़ माँ के नाम" अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण भी किया।

दुग्ध उत्पादन दोगुना करने की दिशा में भोपाल बना नवाचारों का मॉडल

ब्रीडर एसोसिएशन, क्षीर धारा ग्राम योजना और लखपति गौपालक दीदी योजना से पशुपालकों की आय बढ़ाने की पहल

भोपाल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के दुग्ध उत्पादन को दोगुना करने के लक्ष्य को साकार करने के लिए पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा भोपाल जिले में अनेक नवाचारों को प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है। विभाग की इन अभिनव पहलों का उद्देश्य पशुपालकों की आय में वृद्धि करना, उन्नत नस्ल के पशुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा डेयरी क्षेत्र को आत्मनिर्भर और लाभकारी बनाना है।

उपसंचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग डॉ. अभिजीत शुक्ला ने बताया कि जिले में उन्नत नस्ल के दुधारू पशुओं के स्थानीय बाजार को विकसित करने के लिए ब्रीडर एसोसिएशन का गठन किया गया है। वर्तमान में इस एसोसिएशन में 29 सदस्य शामिल हैं तथा इसके संचालन के लिए जिला स्तरीय ब्रीडर प्रकोष्ठ का गठन किया गया है, जिसमें दो शासकीय एवं छह अशासकीय सदस्य शामिल हैं। प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्री अजय सिंह राठौर हैं। इस पहल से पशुपालकों को स्थानीय स्तर पर कम लागत में उच्च गुणवत्ता वाले, स्थानीय जलवायु के अनुरूप तथा अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले पशु उपलब्ध हो सकेंगे। इससे अन्य राज्यों से पशु खरीदने में होने वाले परिवहन व्यय एवं समय की भी बचत होगी।

डॉ. शुक्ला ने बताया कि जिले में क्षीर धारा ग्राम योजना का प्रथम चरण 76 ग्रामों में संचालित किया जा रहा है। यह योजना पांच विभागों के समन्वित प्रयासों से क्रियान्वित की जा रही है। योजना के अंतर्गत पशुओं के स्वास्थ्य परीक्षण, पोषण प्रबंधन, नस्ल सुधार, कृत्रिम गर्भाधान, टीकाकरण, निकृष्ट सांडों का बधियाकरण, बांझपन निवारण शिविर, पात्र पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराना, निराश्रित गौवंश का गौशालाओं में पुनर्वास, चारा विकास तथा जैविक खाद जैसी गतिविधियों को प्राथमिकता दी जा रही है। इससे गांवों में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के साथ पशुधन प्रबंधन को भी सुदृढ़ बनाया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से लखपति गौपालक दीदी योजना प्रारंभ की जा रही है। योजना के तहत अवर्णित गाय एवं भैंसों का गर्भाधान कराया जाएगा, जिससे उच्च उत्पादकता वाली बछिया एवं पड़िया प्राप्त होंगी। वैज्ञानिक पोषण एवं स्वास्थ्य प्रबंधन के साथ इन पशुओं से पारंपरिक नस्लों की तुलना में लगभग ढाई गुना अधिक दूध उत्पादन की संभावना है। इससे प्रत्येक पशुपालक को पशु के जीवनकाल में तीन से चार लाख रुपये तक का अतिरिक्त लाभ प्राप्त हो सकेगा।

डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के अंतर्गत जिले में मध्यम स्तर के डेयरी उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। वर्तमान में पांच पशुपालकों द्वारा 25-25 भैंसों एवं एक पशुपालक द्वारा 25 गायों की क्षमता वाले डेयरी प्रकल्पों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त पैक्स समितियों के माध्यम से 1200 पशुपालक कृषक सदस्यों को पशुपालन किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने की प्रक्रिया भी जारी है, जिससे उन्हें पशुपालन गतिविधियों के विस्तार हेतु आवश्यक वित्तीय सहायता प्राप्त हो सकेगी। पशुपालन एवं डेयरी विभाग की ये पहलें जिले में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने, आधुनिक पशुपालन को बढ़ावा देने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

ब्रीडर एसोसिएशन, क्षीर धारा ग्राम योजना और लखपति गौपालक दीदी योजना से पशुपालकों की आय बढ़ाने की पहल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के दुग्ध उत्पादन को दोगुना करने के लक्ष्य को साकार करने के लिए पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा भोपाल जिले में अनेक नवाचारों को प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है। विभाग की इन अभिनव पहलों का उद्देश्य पशुपालकों की आय में वृद्धि करना, उन्नत नस्ल के पशुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा डेयरी क्षेत्र को आत्मनिर्भर और लाभकारी बनाना है।

उपसंचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग डॉ. अभिजीत शुक्ला ने बताया कि जिले में उन्नत नस्ल के दुधारू पशुओं के स्थानीय बाजार को विकसित करने के लिए ब्रीडर एसोसिएशन का गठन किया गया है। वर्तमान में इस एसोसिएशन में 29 सदस्य शामिल हैं तथा इसके संचालन के लिए जिला स्तरीय ब्रीडर प्रकोष्ठ का गठन किया गया है, जिसमें दो शासकीय एवं छह अशासकीय सदस्य शामिल हैं। प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्री अजय सिंह राठौर हैं। इस पहल से पशुपालकों को स्थानीय स्तर पर कम लागत में उच्च गुणवत्ता वाले, स्थानीय जलवायु के अनुरूप तथा अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले पशु उपलब्ध हो सकेंगे। इससे अन्य राज्यों से पशु खरीदने में होने वाले परिवहन व्यय एवं समय की भी बचत होगी।

डॉ. शुक्ला ने बताया कि जिले में क्षीर धारा ग्राम योजना का प्रथम चरण 76 ग्रामों में संचालित किया जा रहा है। यह योजना पांच विभागों के समन्वित प्रयासों से क्रियान्वित की जा रही है। योजना के अंतर्गत पशुओं के स्वास्थ्य परीक्षण, पोषण प्रबंधन, नस्ल सुधार, कृत्रिम गर्भाधान, टीकाकरण, निकृष्ट सांडों का बधियाकरण, बांझपन निवारण शिविर, पात्र पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराना, निराश्रित गौवंश का गौशालाओं में पुनर्वास, चारा विकास तथा जैविक खाद जैसी गतिविधियों को प्राथमिकता दी जा रही है।

कार्यालय जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या० शिवपुरी (म0प्र0)
कोर्ट रोड शिवपुरी (म.प्र.)
बैलेंस शीट पत्रक वर्षान्त 31 मार्च 2026 की स्थिति पर

गत वर्षान्त पर शेष 31.03.2025		विवरण देनदारियां	इस वर्षान्त पर शेष 31.03.2026	
685,832,668.54	1	**अंशपूंजी**		694,131,619.54
500,000,000.00		(अ) अधिकृत अंशपूंजी	500,000,000.00	
		(ब) अभिदत्त अंशपूंजी		
		अंशो में प्रति अंश रूपय		
		अंशो में प्रति अंश रूपय		
		नाम मात्र के सदस्यों से अंश में		
		(स) प्रदत्त अंशपूंजी		
		अंशो में प्रति अंश रूपय		
		जिसमे से ....बकाया काल्स के कम करने पर		
		नाम मात्र के सदस्यों से अंश में		
		उक्त तीन मे से धारित		
544,463,540.00		1-शासन द्वारा	544,463,540.00	
140,310,243.54		2-समितियों द्वारा	148,606,568.54	
1,058,885.00		3-व्यक्तिगत नाम मात्र सदस्यों द्वारा	1,061,511.00	
1,876,778,944.20	2	**आरक्षित निधि एवं अन्य रिजर्व :-**		313,978,562.74
28,381,167.48		रक्षित कोष	28,381,167.48	
17,572,897.10		कृषि साख स्था. निधि	17,572,897.10	
42,949,212.90		भवन निधि	42,949,212.90	
6,621,375.72		वाहन निधि	6,621,375.72	
1,182,578.72		प्रशिक्षण निधि	1,182,578.72	
2,949,636.59		सहकारी विकास निधि	2,949,636.59	
6,759,479.35		अंश विमोचन रिजर्व	6,759,479.35	
115,149,000.00		रिवेल्यूवेशन फिक्स असेट फण्ड	115,149,000.00	
10,119,500.00		विनियोग अस्थिरता संचय	10,119,500.00	
-		विशेष डूबन्त संदिग्ध निधि हेतु प्रावधान	-	
-		संदिग्ध एवं डूबंत ग्रामीण क्षेत्र	-	
1,551,011,948.30		डूबन्त एवं संदिग्ध निधि हेतु प्रावधान	-	
34,483.67		स्टेन्डर्ड असेस्टस हेतु प्रावधान	0.00	
11,753,949.49		सबस्टेन्डर्ड असेस्टस हेतु प्रावधान	-	
67,233.25		लाभांश समीकरण निधि हेतु प्रावधान	67,233.25	
60,904.00		विनियोजित निधियां हेतु प्रावधान	60,904.00	

गत वर्षान्त पर शेष 31.03.2025		विवरण लेनदारियां (सम्पत्ति एवं आस्तियां)	इस वर्षान्त पर शेष 31.03.2026	
		सिलक एवं बैंक बैलेस		
4,947,317.00	1	**नगद रोकड़ तिजोरी में तथा रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, स्टेट बैंक, सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक, राज्य सहकारी बैंक**		14,623,692.00
180,268,731.84	2	**सिलक अन्य बैंकों मे**		196,712,134.70
		1-चालू अमानत		
15,771,381.91		अ-भारतीय स्टेट बैंक	90,976,232.50	
140,122,945.64		ब-अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक	44,485,634.17	
24,374,404.29		स-म0 प्र0 राज्य सहा बैंक	61,250,268.03	
547,719,461.99		2-मुद्दती अमानत		90,422,486.00
505,019,699.00		अ-म0 प्र0 राज्य सहक बैंक	45,019,699.00	
31,851,114.00		ब-रक्षित निधि शीर्ष बैंक	34,001,064.00	
1,000,000.00		स-भारतीय स्टेट बैंक	1,000,000.00	
0.00		द-अन्य सावधि जमा	0.00	
9,848,648.99		इ-सेन्ट्रल बैंक	10,401,723.00	
	3	**मांग और अल्प सुचना पर प्रतिदेय राशि**		
628,400,000.00	4	**विनियोग**		619,574,000.00
584,000,000.00		1-केन्द्रीय एवं राज्य शासन की प्रतिभतियो	565,624,000.00	
-		2-अमानती प्रतिभूतियो मे	-	
44,400,000.00		3-सहकारी संस्थाओ के अंशो मे	53,950,000.00	
	5	**ऋण एवं अग्रिम**		3,307,902,260.98
2,739,925,050.71		अ-अल्पावधि ऋण, नगदी साख, अधिविकर्ष तथा विलो मे	3,307,902,260.98	
		1-शासकीय प्रतिभूतियों		
		2-अन्य ठोस प्रतिभूतियो पर		
		3-व्यक्तिगत ऋण वांकी		
		4-कालातीत वांकी		
		5-अवमानक संदिग्ध डूबन्त ऋण		
113,364,096.61		ब-मध्यकालीन	116,395,538.37	116,395,538.37
		1-इसमे से शासकीय प्रतिभूतियों पर		

गत वर्षान्त पर शेष 31.03.2025		विवरण देनदारियां	इस वर्षान्त पर शेष 31.03.2026	
31,806,357.01		कर्मचारी उपादान	31,806,357.01	
16,825.64		सामान्य हितनिधि	16,825.64	
1,997.00		धर्मार्थ निधि	1,997.00	
807.00		कर्मचारी हितनिधि	807.00	
28,967.38		वोनस रिजर्व हेतु प्रावधान	28,967.38	
-		अन्य निधियां हेतु प्रावधान	-	
-		केपीटल रिजर्व हेतु प्रावधान	-	
50,237,000.00		अन्य प्रावधान	50,237,000.00	
73,623.60		केपीटल रिजर्व अन्य	73,623.60	
3,058,194,735.35	**3**	**अमानते :**		2,846,648,369.26
1,035,953,050.64		(अ) मुद्दती अमानते	904,211,555.75	
926,868,608.18		1-व्यक्तिगत अमानते	795,418,450.29	
-		2-केन्द्रीय सहकारी बैंक		
109,084,442.46		3-अन्य सहकारी समितियां	108,793,105.46	
1,946,559,612.72		(ब) बचत अमानते	1,866,473,716.52	
1,619,482,887.38		1-व्यक्तिगत अमानते	1,529,591,750.57	
-		2-केन्द्रीय सहकारी बैंक	-	
327,076,725.34		3-अन्य सहकारी समितियां	336,881,965.95	
75,682,071.99		(स) चालू अमानते	75,963,096.99	
30,312,421.55		1-व्यक्तिगत अमानते	31,727,288.55	
-		2-केन्द्रीय सहकारी बैंक	-	
45,369,650.44		3-अन्य सहकारी समितियां	44,235,808.44	
-		(द) आहूत एवं अल्पकालीन अमानते		
642,892,750.00	**4**	**उधार**		1,071,779,222.00
		भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, राज्य सहकारी बैंक		
639,000,000.00		(अ) अल्पकालीन ऋण नगद साख, अधिविकर्ष तथा बिलो मे इनमे से अन्य ठोस प्रतिभूति पर	1,067,886,472.00	
3,892,750.00		(आ) मध्यम अवधि ऋण इसमे शासन प्रतिभूतियो पर , इनमे से अन्य ठोस	3,892,750.00	
-		(इ) दीर्घकालीन	-	
13,229,270.00	**5**	**देने योग्य बिल :**		13,229,270.00
(248,444,383.65)	**6**	**शाखाओ का जमाखर्चः**		(251,213,676.95)
228,660,931.06	**7**	**कालातीत ब्याज रिजर्व**		228,660,931.06
82,414,396.83	**8**	**ब्याज देय**		70,685,237.16
(1,512,107,542.50)	**9**	**अन्य देनदारियां**		(263,585,277.58)
15,306,373.03		अ-सस्पेंश		15,306,373.03

गत वर्षान्त पर शेष 31.03.2025		विवरण लेनदारियां (सम्पत्ति एवं आस्तियां)	इस वर्षान्त पर शेष 31.03.2026	
		2-अन्य ठोस प्रतिभूतियो पर		
		3-व्यक्तिगत ऋण वांकी		
		4-कालातीत वांकी		
1,853,853.00		स-दीर्घावधि	2,030,743.00	2,030,743.00
		1-इसमे से शासकीय प्रतिभूतियों पर		
		2-अन्य ठोस प्रतिभूतियो पर		
		3-व्यक्तिगत ऋण वांकी		
		4-कालातीत वांकी		
133,237,158.54	**6**	**ब्याज लेना वांकी**	132,390,760.54	132,390,760.54
		1-कालातीत ऋणो पर		
		2-चालू ऋणो पर		
		3-ऋण राहत शासन से		
1,577,769.00	**7**	**बिल्स रिसीवएवल एज पर कान्ट्रा**	1,577,769.00	1,577,769.00
-	**8**	**शाखा समायोजन**	-	
174,054.44	**9**	**भवन**		156,649.44
1,048,867.56		1-पुस्तक मूल्य	1,048,867.56	
874,813.12		2-कम किया अवक्षयण	892,218.12	
1,265,125.22	**10**	**साज सज्जा**		1,138,612.22
5,593,979.58		1-पुस्तक मूल्य	5,593,979.58	
4,328,854.36		2-कम किया अवक्षयण	4,455,367.36	
474,072.11	**11**	**कम्प्यूटर**		284,443.11
5,659,318.50		1-पुस्तक मूल्य	5,659,318.50	
5,185,246.39		2-कम किया अवक्षयण	5,374,875.39	
68,800.10	**12**	**ऑफिस इक्यूपमेंट**		61,920.10
204,476.24		1-पुस्तक मूल्य	204,476.24	
135,676.14		2-कम किया अवक्षयण	142,556.14	
899,601.76	**13**	**वाहन**		764,661.76
2,631,387.00		1-पुस्तक मूल्य	2,631,387.00	
1,731,785.24		2-कम किया अवक्षयण	1,866,725.24	
115,149,000.00	**14**	**भूमि**		115,149,000.00
358,127,677.51	**15**	**अन्य लेनदारियां**		125,129,586.01
1,954.00		1-अनाज अग्रिम स्टाफ	-	
55,111.00		2-वेतन / प्रवास अग्रिम	-	
550.00		3-त्यौहार अग्रिम	-	
1,731,068.22		4-टीडीएस	1,760,668.22	

गत वर्षान्त पर शेष 31.03.2025		विवरण देनदारियां	इस वर्षान्त पर शेष 31.03.2026	
(1,527,413,915.53)		ब-विविध देनदारियां		(278,891,650.61)
72,237,355.24		1-सण्ड्रीक्रेडिटर्स	78,614,538.53	
93,594.48		2-फुटकर देनदारियां	(2,120,904.52)	
510,266.00		3-अंकेक्षण शुल्क	1,210,348.00	
8,493,698.58		4- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के देय	8,201,866.34	
20,988,717.57		5- लैव्ही	14,003,493.96	
4,037,220.46		6- कैश केडिट खाद	4,757,045.35	
352,135.45		7- कैश केडिट विपणन	352,135.45	
470,719.85		8- म्यादी अमा० के तारण पर ऋण	75,753.85	
(1,367.50)		9-शासकीय ऋण ज्वाइंट फार्मिग	11,502.50	
168,510.00		10-वोनस देय	168,510.00	
23,293.75		11-वेतन देय	23,293.75	
40,055.81		12-प्रोत्साहन राशि	40,055.81	
(31,435,620.77)		13-संवर्ग निधि	(33,668,690.77)	
932,573.82		14-भविष्य निधि कर्मचारी	616,088.82	
19,817.00		15-बचत बैंक गारंटी	19,817.00	
374,167.25		16-परिवार कल्याण कोष	392,839.25	
(25,415.25)		17-समूह बीमा	(27,299.25)	
64,781.00		18-एलआईसी	73,600.00	
193,237,304.06		19-फर्टीलाइजर सेल्स कलेक्शन	94,711,125.92	
2,714,162.00		20-टीडीएस पेविल	1,007,825.23	
70,261.36		22-जीएसटी पबिल	(28.64)	
3,590,942.00		23-सर्विस टेक्स	4,301,173.00	
1,100,808,881.77		24-अन्य दायित्व	939,219,304.83	
(156,152,938.11)		25-नेफ्ट अन्तर	(152,123,352.94)	
-		26- किसान क्रेडिट कार्ड सामान्य “अ” वर्ग	1,823,366.31	
-		27- किसान क्रेडिट कार्ड सामान्य “ब” वर्ग	3,446,445.70	
-		28- किसान क्रेडिट कार्ड तिलहन “अ’ वर्ग	625,062.25	
-		29- किसान क्रडिट कार्ड तिलहन”ब’’ वर्ग	5,431,826.28	
-		30- प्रावधान for RBI Penality	22,800,000.00	
-		31- स्टेन्डर्ड असेस्टस हेतु प्रावधान	1,644,108.74	
-		32- सबस्टेन्डर्ड असेस्टस हेतु प्रावधान	580,834.21	
-		33- डूबन्त एवं संदिग्ध निधि हेतु प्रावधान	2,267,615,472.66	
-		34-छात्रवृति	-	
(2,749,027,031.35)		35-लाभ/हानि	(3,542,718,808.23)	
4,827,451,769.83			-	**4,724,314,257.23**

गत वर्षान्त पर शेष 31.03.2025		विवरण लेनदारियां (सम्पत्ति एवं आस्तियां)	इस वर्षान्त पर शेष 31.03.2026	
-		5-अग्रिम आयकर	-	
8,561,624.30		6-जीएसटी इनपुट	10,320,268.56	
515,478.07		8-लेखन सामग्री	550,488.02	
26,307.33		9-पुस्तकालय	26,307.33	
967,106.45		10-फार्स एवं पंजियां	827,523.67	
722,475.00		11- Clearing house	722,475.00	
2,394,708.07		12-संडीडेटर्स	2,388,071.00	
9,990,682.17		13-अन्य	9,990,782.17	
30,418,253.30		14-एल आई सील टस्टी फण्ड	30,418,253.30	
-		15-लाभांश प्राप्य एपेक्स बैंक	-	
473,250.00		16-प्रीमियम परिशोधन	555,513.00	
16,431,842.58		17-उपार्जित ब्याज	16,436,356.65	
2,969,203.64		18-राज्य शासन डीएमआर राशि प्राप्य	2,969,203.64	
2,809,506.00		19-केडर फण्ड वेतन समिति प्रबंधक	2,809,506.00	
6,700,042.51		20-केडर फण्ड वसूली योग्य	6,700,042.51	
1,617.32		21-लेव्ही पूल फण्ड	1,617.32	
567,969.00		22-शीर्ष बैंक से लेना शेष	567,969.00	
296,603.10		23-जवाहर रोजगार योजना	296,603.10	
11,502.50		24-संयुक्त ऋण ज्वाइंट फार्मिंग	11,502.50	
12,501,997.37		25 अन्य सम्पत्ति	16,898,554.68	
3.34		26-सिक्योरिटी सेटलमेंट	3.34	
72,693.00		27-अन्य व्यवसायिक सम्पत्ति	72,693.00	
13,574,376.00		28-शासन से मूल लेना	13,574,376.00	
7,230,808.00		29-शासन से ब्याज लेना	7,230,808.00	
239,100,945.24		30-पेक्स से लेना	-	
4,827,451,769.83				**4,724,314,257.23**

कार्यालय जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या० शिवपुरी (म०प्र०)
कोर्ट रोड शिवपुरी (म.प्र.)
लाभ हानि पत्रक वर्ष 2025-26

गत वर्षान्त पर शेष 3/31/2025		आय	इस वर्षान्त पर शेष 3/31/2026
67,635,436.88	1	**ब्याज एवं छट**	242,213,120.80
33,992.90	2	कमीशन, विनिमय एवं दलाली	567,222.81
-	3	सब्सिडी तथा अनुदान	-
-	4	गैर बैंकिंग आस्तियों से हुई आय तथा ऐसी आस्तियों की बिक्री अथवा लेनदेन से हुआ लाभ	-
5,570,489.97		**अन्य प्राप्तियां**	6,016,626.15
73,239,919.75		**योग :**	**248,796,969.76**

कार्यालय जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या शिवपुरी (म0प्र0)
कोर्ट रोड शिवपुरी (म.प्र.)
लाभ हानि पत्रक वर्ष 2025-26

गत वर्षान्त पर शेष 3/31/2025		व्यय	गत वर्षान्त पर शेष 3/31/2026
302,861,915.04	1	ब्याज दिया अमानत व ऋण पर	227,852,954.33
19,400,223.90	2	वेतन व भत्ते एवं भविष्य निधि	39,144,058.44
-	3	संचालक मण्डल एवं स्थानीय समितियों के सदस्यों का शुल्क एवं भत्ते	-
1,325,303.00	4	किराया, शुल्क, बीमा, बिजली आदि	920,737.00
478,500.00	5	विधि व्यय	392,000.00
-	6	आयकर	-
-	7	th,lVh isM	-
27,750.00	8	डाक, दूरलेख एवं दूरभाष	40,087.00
875,329.00	9	अंकेक्षण शुल्क	1,521,679.00
642,354.00	10	संपत्ति पर अवक्षयण एवं दुरूस्ती	475,367.00
173,382.23	11	लेखन सामग्री छपाई तथा विज्ञापन	319,509.02
(56,544,813.39)	12	मानक संदिग्ध एवं डूबत ऋण हेतु प्रावधान	44,001,403.49
556,958,077.97	13	कालातीत ब्याज हेतु प्रावधान	716,603,524.36
10,911,914.06	14	अन्य व्यय	11,217,427.00
-	15	ग्रेच्यूटी बैंक कर्मचारी	-
(763,870,016.06)	16	लाभ जो बैलेन्सशीट में ले जाया गया	(793,691,776.88)
73,239,919.75		**योग :**	**248,796,969.76**

ATUL KUMAR & ASSOCIATES

CHARTERED ACCOUNTANTS
CITY CENTRE, GWALIOR (M.P.)- 474011
Email : atul.ca2001@gmail.com - Mob : 9425110919
GSTIN : 23AADFA9457A1ZU

AUDIT CLASSIFICATION OF JILA SAHAKARI KENDRIYA BANK MARYADIT, SHIVPURI

Audit Classification for the Financial year 2025-26 is done as per the norms prescribed by the National Bank for Agriculture and Rural Development Department of supervision and according to guidelines issued by the NABARD, the rating to the bank is given "D" as follows :

SUMMARY OF MARKS

S.NO.	PARAMETER	MAXIMUM MARKS	MARKS OBTAINED
1.	Capital Adequacy	15	0
2.	Asset Quality	15	5
3.	Management	10	0
4.	Earning	10	0
5.	Liquidity	15	6.5
6.	Systems and Control	20	11.5
7.	Compliance	15	10
	TOTAL	100	33

For Atul Kumar & Associates
Chartered Accountants
(FRN :- 001982C)

ATUL KUMAR & ASSOCIATES GWALIOR CHARTERED ACCOUNTANT

CA NEHA GARG (MS 415128)
PARTNER
UDIN: 26415128KNZXST2991
Date: 20.05.2026
Place: Gwalior

पंजीयन क. भोपाल 128 दिनांक 15.12.1971 मा.रि.बैंक लायसेन्स क. एम.पी./1753 दिनांक 19/06/2000

व्यवसायिक एवं औद्योगिक सहकारी बैंक लि. मुरैना (म.प्र.) प्रपत्र (अ)

तीसरी तालिका बैंकिंग रेग्यूलेशन एक्ट – 1949 की धारा 29 के अंतर्गत
स्थिति विवरण – पत्रक वर्ष 2025–26 वर्षान्त 31.03.2026

गत वर्ष की रकम (2024–25)	रकम (31.03.2025)	पूंजी एवं देनदारियां	अंकेक्षण वर्ष की रकम(2025–26)	रकम (31.03.2026)	गत वर्ष की रकम (2024–25)	रकम (31.03.2025)	संपत्ति एवं आस्तियां	अंकेक्षण वर्ष की रकम(2025–26)	रकम (31.03.2026)
40561700.00		(1) अंश पूंजी		50846200.00	44696571.14		(1) रोकड़		56661063.64
		(अ) अधिकृत अंश पूंजी				20029135.00	1. नगदी रोकड़	16087749.00	
		रू. 50000000.00 प्रति अंश				0.00	2. भारतीय रिजर्व बैंक	0.00	
		मूल्य रू. 100.00 अंशपूंजी में से				11956960.04	3. भारतीय स्टेट बैंक	22127037.04	
	40561700.00	(1) संदस्यों की ओर	50846200.00			12710476.10	4. शीर्ष सह. बैंक	18446277.60	
		(2) राज्य शासन				0.00	5. रेवेन्यू स्टाम्प	0.00	
511338003.64		(2) रक्षित एवं अन्य निधियां		574022302.28	326179492.22		(2) अन्य अधिकोषों में		289739830.47
	52315492.75	1. रक्षित निधि	55704996.75			83112959.22	1. चालू खाता	92351167.47	
	71069760.91	2. भवन कोष	75137166.55			0.00	2. बचत खाता	0.00	
	360491840.72	3. संदिग्ध एवं डूबन्त कोष	395976055.72			243066533.00	3. म्यादी खाता	197388663.00	
	879319.00	4. वाहन कोष	879319.00		71695950.00		(3) शीर्ष एवं सह. बैंकों में म्यादीं जमा		90727319.00
	1194935.35	5. धर्मादा कोष	1291778.35			0.00	1. जिला सह. केन्द्रीय बैंक	20000000.00	
	634148.00	6. कर्म. सहायता कोष	634148.00			71695950.00	2. शीर्ष सह. बैंक	70727319.00	
	378428.76	7. सह. विकास समाज कल्याण	378428.76		797111933.57		(4) शासकीय प्रतिभूतियां		944343426.17
	14942239.15	8. लाभांश समानीकरण निधि	15910669.15			797111933.57	शासकीय प्रतिभूतियां	944343426.17	
	3950000.00	9. मानक आस्तियां	3950000.00		100.00		(5) संस्थाओं में विनियोजन		100.00
	4723001.00	10. विनियोजन विकास निधि	23207216.00			100.00	1. जिला सह. केन्द्रीय बैंक	100.00	
	758838.00	11.कर्मचारी प्रशिक्षण निधि	952524.00		1039356419.07		(6) ऋण एवं अग्रिम		1076595308.75
1713123429.53		(3) अमानतें		1803250738.12		715521386.68	1. अल्पकालीन ऋण	812021646.65	
	1179793704.57	1. मुद्दती अमानत	1254874646.57			33526972.85	2. मध्यकालीन ऋण	47803789.08	
	511547053.11	2. बचत अमानत	531815294.71			290308059.54	3. दीर्घकालीन ऋण	216769873.02	
	20778145.03	3. चालू अमानत	15234907.89		484666096.83		(7) प्राप्ती योग्य ब्याज		392894849.58
	1004526.82	4. जमा ऋण खाता	1325888.95			456506934.27	1. ऋणों पर	366926687.02	
456509714.27	456509714.27	(4) अतिदेय प्रारक्षित निधि	366929467.02	366929467.02		28159162.56	2. अमानतों पर	25968162.56	
16842595.00	16842595.00	(5) ब्याज देय अमानतों पर	16854377.00	16854377.00	1970711.64		(8) स्थायी सम्पत्ति		2975176.90
35273120.30		(6) अन्य देनदारियां		42457232.32		505697.00	1. फर्नीचर	1551967.20	
	1457157.00	1 ऑडिट फीस	1659157.00			20628.02	2. कम्प्यूटर हार्डवेयर	14315.75	
	64236.00	2 डी.डी. इस्यू	55460.00			848136.62	3. इलेक्ट्रिकल आईटम	892143.95	
	1125602.75	3 पे ऑर्डर	1300271.12			596250.00	4. सिविल वर्क	516750.00	
	9166211.00	4 सस्पेन्स क्रेडिटर्स	6363688.00		17655586.91		(9) अन्य सम्पत्तियां		23913033.51
	15000000.00	5 बैंक आयकर	25000000.00			20145.00	1. बैंक वाहन	188220.00	
	686017.00	6 चंदा जिला सह. संघ	686017.00			59648.50	2. स्टॉक फार्म	25355.83	
	0.35	7. एस.जी.एस.टी.	0.00			12555002.00	3. अग्रिम आयकर बैंक	22677001.00	

(96)

	2419484.19	8. कर्मचारी एक्सग्रेसिया	2419484.19			815025.06	4. प्राप्ति योग्य (डीफ) राशि	114997.86	
	3719412.01	9.लायबिलिटीज	3338155.01			314138.95	5. सी.जी.एस.टी. रिसीयेवल	453729.41	
	1635000.00	10.विनियोजन अवक्षयण निधि	1635000.00			308478.30	6.एस.जी.एस.टी. रिसीयेवल	453729.41	
93475035.05		(7) कोन्ट्रा मद		97063918.38		233196.30	7. आई.जी.एस.टी. रिसीयेवल	0.00	
	14592839.52	1. लीव इन कैशमेन्ट	15590086.17			350000.00	एडवान्स खाता	0.00	
	17600552.53	2. ग्रेच्यूटी फंड	19922722.21			2999952.80	8. इनवर्ड आर.टी.जी.एस.	0.00	
	55950288.00	3. अनक्लेम्ड डिपोजिट कस्टूमर	53528020.00		93475035.05		(10) कोन्ट्रा मद		97063918.38
	5331355.00	4.देय वसूली खर्चे	8023090.00			5331355.00	प्राप्ति योग्य वसूली खर्चे	8023090.00	
9684298.64		(8) लाभ		23489791.28		14592839.52	2. लीव इनकैशमेन्ट	15590086.17	
	9684298.64	शुद्ध लाभ	23489791.28			17600552.53	3. ग्रेच्यूटी फंड	19922722.21	
						55950288.00	4. डीफ फंड विथ आर.बी.आई.	53528020.00	
2876807896.43	2876807896.43	योग	2974914026.40	2974914026.40	2876807896.43	2876807896.43	योग	2974914026.40	2974914026.40

कार्यालय संयुक्त पंजीयन सहकारी संस्थायें चंबल संभाग मुरैना
संपरीक्षा प्रतिवेदन तथा निर्गमन पत्र
क्रमांक/अंके./निर्गमन/ 488 दिनांक 01/06/26
... निर्देशों के पालन हेतु जारी

शाखा लेखापाल
व्यव. एवं औद्यो. सह. बैंक लि. मुरैना

प्र. शाखा प्रबंधक
व्यव. एवं औद्यो. सह. बैंक लि. मुरैना

संयुक्त पंजीयक
सहकारी संस्थाऐं
चम्बल संभाग, मुरैना

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
व्यव. एवं औद्यो. सह. बैंक लि. मुरैना

सहायक पंजीयक (अंके०)
सहकारी संस्थाऐं मुरैना

अंकेक्षण टीप की गणितीय दृष्टि से जांच की गई, सही पाया गया
अंकेक्षक के हस्ताक्षर....
नाम एवं पद....

व्यव. एवं औद्यो. सह. बैंक लि. मुरैना

अंकेक्षण टीप की गणितीय दृष्टि से जांच की गई, सही पाया गया
अंकेक्षक के हस्ताक्षर....
नाम एवं पद....

संचालक
व्यव. एवं औद्यो. सह. बैंक लि. मुरैना

संचालक
व्यव. एवं औद्यो. सह. बैंक लि. मुरैना

उप पंजीयक
सहकारी संस्थाऐं मुरैना

अध्यक्ष
व्यव. एवं औद्यो. सह. बैंक लि. मुरैना

व्यवसायिक एवं औद्योगिक सहकारी बैंक लि. मुरैना (म.प्र.)

लाभ–हानि पत्रक वर्ष 2025–26 (31.03.2026)

(प्रपत्र ब)

गत वर्ष की रकम (2024–25)	रकम (31.03.2025)	लाभ के मद	गत वर्ष की रकम (2025–26)	रकम (31.03.2026)	अंकेक्षण वर्ष की रकम (2024–25)	रकम (31.03.2025)	हानि के मद	अंकेक्षण वर्ष की रकम (2025–26)	रकम (31.03.2026)
189804356.14	189804356.14	ब्याज एवं छूट	230480359.20	230480359.20	90404986.00	90404986.00	ब्याज दिया अमानतों पर	99294263.90	99294263.90
5464713.89	5464713.89	अन्य प्राप्तीयां	10656380.79	10656380.79	18445745.00	18445745.00	वेतन, उपवेतन, भविष्य निधि आदि	20007096.00	20007096.00
					43300.00	43300.00	संचालक बैठक शुल्क	147075.00	147075.00
					1000000.00	1000000.00	अंकेक्षण शुल्क	1610000.00	1610000.00
					5010121.50	5010121.50	किराया शुल्क, बीमा, प्रकाश आदि	5049708.88	5049708.88
					9701.00	9701.00	कानूनी सलाह शुल्क	342200.00	342200.00
					125119.00	125119.00	डाक दूरभाष, टेलीफोन, आदि	119393.00	119393.00
					789104.16	789104.16	लेखन सामग्री, छपाई, विज्ञापन आदि	876898.00	876898.00
					508978.90	508978.90	संपत्ति अवक्षयण, दुरूस्ती	619337.32	619337.32

					11747715.83	11747715.83	विविध व्यय, सी.बी.एस. सोफ्टवेयर चार्जज, कन्टनजेंसी,आमसभा, बैंक वाहन, प्रीमि. शास. प्रतिभूति, इन्सी. क्लीयरिंग हाउस, ए.एम.सी, प्रशा. प्रभार, लीगल स्टाम्प फीस, कम्प्यू. एण्ड हार्डवेयर, रिपे. मेन्ट., लीव इन. कैश. कर्म. ग्रेच्युटी, कमीशन जनता डिपो. वसूली खर्चे, बैंक आयकर गत वर्ष, बैंक वेब व्यय, गुड्स एण्ड सर्विस टेक्स, आदि	11580976.61	11580976.61
					15000000.00	15000000.00	प्रावधान बैंक आयकर	25000000.00	25000000.00
					42500000.00	42500000.00	प्रावधान संदिग्ध एवं डूबंत कोष	35000000.00	35000000.00
							प्रावधान इन्वेस्टमेंन्ट फ्लेक्च्युशन रिजर्व	18000000.00	18000000.00
					9684298.64	9684298.64	लाभ वर्ष 2025–26	23489791.28	23489791.28
195269070.03	195269070.03	योग	241136739.99	241136739.99	195269070.03	195269070.03	योग	241136739.99	241136739.99

शाखा लेखापाल
व्यव. एवं औद्यो. सह. बैंक
लि. मुरैना

प्र. शाखा प्रबंधक
व्यव. एवं औद्यो. सह. बैंक
लि. मुरैना

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
व्यव. एवं औद्यो. सह. बैंक
लि. मुरैना

सनदी लेखाकार
व्यव. एवं औद्यो. सह. बैंक
लि. मुरैना

संचालक
व्यव. एवं औद्यो. सह. बैंक
लि. मुरैना

संचालक
व्यव. एवं औद्यो. सह. बैंक
लि. मुरैना

अध्यक्ष
व्यव. एवं औद्यो. सह. बैंक
लि. मुरैना

SPJV & Co. BHOPAL Chartered Accountants

नाम संस्था– व्यवसायिक एवं औद्योगिक सहकारी बैंक लि. मुरैना (म.प्र.)

अंकेक्षण प्रमाण – पत्र

(जो लागू न हो उन्हें काट दें)

वर्ष : 2025–26

1.x संस्था के अंकेक्षण के दौरान प्राप्त गवन–धोखाधड़ी, गंभीर वित्तीय अनियमितताओं व सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों में उल्लंघन के प्रकरणों का उल्लेख मेरे द्वारा अंकेक्षण में कर दिया गया है।

2.x यह कि ऐसी वित्तीय अनियमिततायें जिनसे संस्था को हानि पहुँची है कि बसूली हेतु विशेष प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है।

3.x यह कि गवन धोखाधड़ी के प्रकरणों में पुलिस कार्यवाही हेतु तथा राशि बसूली हेतु संबंधितों को अवगत करा दिया गया है।

4. अंकेक्षण के दौरान गबन–धोखाधड़ी गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के कोई प्रकरण प्रकाशमान नहीं हुये।

5. संपरीक्षा प्रतिवेदन में उल्लेखित आपत्तियों के अतिरिक्त अन्य कोई महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाशमान नहीं हुये हैं।

6. संस्था को अंकेक्षण वर्ष के लिये वर्ग "अ" प्रदान किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक : 13.05.2026
स्थान – मुरैना (म.प्र.)

कार्यालय संयुक्त पंजीयन सहकारी संस्थायें चंबल संभाग मुरैना
संपरीक्षा प्रतिवेदन तथा निर्गमन पत्र क्रमांक/अंके./निर्गमन/488 दिनांक 04/06/26 में उल्लेखित आक्षेपों ... के पालन हेतु जारी

संयुक्त पंजीयक
सहकारी संस्थायें
चम्बल संभाग, मुरैना

वैधानिक अंकेक्षक
एस.पी.जे.व्ही. एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार
FRN : 116884W

पीयूष चतर
भागीदार
M. No. 410901
UDIN: 26410901FXCQUL3478

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ, भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन

भोपाल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल में गरिमामय योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संघ के प्रबंध संचालक श्री ऋतुराज रंजन, महाप्रबंधक श्री संजय सिंह, हस्तशिल्प केंद्र के सहायक निदेशक श्री नरसिंह सैनी सहित संघ के अधिकारी एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए सामूहिक योगाभ्यास किया।

इस अवसर पर हस्तशिल्प केंद्र तथा सोसाइटी फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट भोपाल के अधिकारी एवं कर्मचारियों ने भी कार्यक्रम में भाग लेकर योगाभ्यास किया तथा स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया।

कार्यक्रम के दौरान योग के शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। वक्ताओं ने कहा कि नियमित योगाभ्यास न केवल शरीर को स्वस्थ एवं सुदृढ़ बनाता है, बल्कि मानसिक तनाव को दूर कर सकारात्मक ऊर्जा, आत्मविश्वास एवं कार्य क्षमता में भी वृद्धि करता है। उपस्थित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपने दैनिक जीवन में योग को नियमित रूप से अपनाने के लिए प्रेरित किया गया।

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करना, कार्यस्थल पर सकारात्मक एवं ऊर्जावान वातावरण का निर्माण करना तथा समाज में योग के प्रति व्यापक जन-जागरूकता विकसित करना रहा। कार्यक्रम के समापन पर सभी प्रतिभागियों ने "करें योग, रहें निरोग" के संदेश को जन-जन तक पहुँचाने तथा योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाने का सामूहिक संकल्प लिया।

जबलपुर प्रवास के दौरान अपेक्स बैंक प्रशासक ने संभागीय समीक्षा बैठक में दिए निर्देश

जबलपुर। अपेक्स बैंक के प्रशासक श्री महेंद्र सिंह यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 को "कृषक कल्याण वर्ष" के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इसी के अनुरूप प्रदेश की सहकारी बैंकिंग व्यवस्था किसानों के हित में प्रभावी ढंग से कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि अपेक्स बैंक, जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों एवं प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) के माध्यम से पात्र किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर एक वर्ष की अवधि के लिए 3 लाख रुपये तक का कृषि ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। जबलपुर प्रवास के दौरान अपेक्स बैंक, जबलपुर के सभागार में आयोजित जबलपुर संभाग के जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। श्री यादव ने कहा कि सहकारी बैंक आज किसानों के सबसे बड़े सहयोगी बनकर उभरे हैं। यह ऋण सुविधा किसानों को खाद, बीज, उर्वरक तथा अन्य कृषि आवश्यकताओं की पूर्ति में आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है, जिससे उन्हें निजी साहूकारों एवं महंगे ब्याज वाले ऋणों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और खेती की लागत कम करने में भी सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शीघ्र ही ऐसी नीति लाने की दिशा में कार्य कर रही है, जिससे किसानों के डिफॉल्टर बनने की स्थिति में कमी आए और उन्हें समय पर आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध हो सके।

बैठक में श्री यादव ने सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को नियमित रूप से पैक्स एवं समितियों का भ्रमण करने, अधिकाधिक किसानों को सहकारी व्यवस्था से जोड़ने तथा सदस्यता अभियान में उल्लेखनीय प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सदस्यता अभियान एवं ऋण वितरण की सतत समीक्षा कर योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र किसान तक पहुँचाया जाए।

बैठक में संयुक्त आयुक्त श्री राकेश पांडे, प्रशासक के ओएसडी श्री अभय प्रधान, अपेक्स बैंक की संभागीय शाखा प्रबंधक श्रीमती किरण साहू, जबलपुर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री नितेश जिंदल, छिंदवाड़ा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री राजेश रैकवार, सिवनी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री के.के. सोनी सहित जबलपुर संभाग के सभी जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उपस्थित रहे।

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ, भोपाल में 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित

भोपाल। पर्यावरण संरक्षण, हरित आवरण में वृद्धि तथा प्रकृति के प्रति जन-जागरूकता विकसित करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल द्वारा 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में संघ के प्रबंध संचालक श्री ऋतुराज रंजन, महाप्रबंधक श्री संजय सिंह, हस्तशिल्प केंद्र के सहायक निदेशक श्री नरसिंह सैनी सहित मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ, हस्तशिल्प केंद्र तथा सोसाइटी फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, भोपाल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सहभागिता करते हुए परिसर में विभिन्न प्रजातियों के पौधों का रोपण किया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सामाजिक दायित्व ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। उन्होंने सभी से अधिक से अधिक वृक्ष लगाने तथा उनके संरक्षण एवं संवर्धन का संकल्प लेने का आह्वान किया।

कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता के संवर्धन तथा स्वच्छ एवं हरित वातावरण के निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल एवं संरक्षण का सामूहिक संकल्प लिया।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक गणेश प्रसाद मांझी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : गणेश प्रसाद मांझी
डॉक पंजीयन क्रमांक : म.प्र./भोपाल/357/2021-23 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2926159, 2926160, इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।